

भूमि अभलिखों का डिजिटलीकरण

यह एडिटोरियल 17/05/2023 को 'हाइटी बजिनेस लाइन' में प्रकाशित "Digitisation of land records is hugely beneficial" लेख पर आधारित है। इसमें भूमि अभलिखों के डिजिटलीकरण के महत्व और उनके संभावित लाभों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

[विशेष आरथिक क्षेत्र \(SEZ\)](#), [राष्ट्रीय भूमि अभलिख आधुनिकीकरण कार्यक्रम \(NLRMP\)](#), [डिजिटल इंडिया भूमि अभलिख आधुनिकीकरण कार्यक्रम \(DILRMP\)](#)

मेन्स के लिये:

भूमि अभलिखों का डिजिटलीकरण, DILRMP योजना: लाभ, चुनौतियाँ और आगे की राह

भूमि (Land) कसी भी देश के लिये एक मूल्यवान परसिंपत्ति होती है और भारत जैसे देश के लिये तो यह और भी मूल्यवान है जहाँ 50% से अधिक कार्यशील आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। इस परिवृत्ति में एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभलिख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में 'डिजिटल इंडिया भूमि अभलिख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernization Programme- DILRMP)' के प्रवर्तन के माध्यम से पूरववर्ती राष्ट्रीय भूमि अभलिख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Land Record Modernization Programme- NLRMP) को नया रूप प्रदान किया।

भूमि का महत्व

- आजीविका का स्रोत:** भूमि भिन्न रूपों सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को प्रयावास और भरण-पोषण प्रदान करती है। भारत में 50% से अधिक कार्यशील आबादी कृषि कार्य से संलग्न है, जो प्राथमिक संसाधन के रूप में भूमि पर निर्भर करती है।
 - भूमि का उपयोग वानकी, खनन और अन्य गतिविधियों के लिये भी किया जाता है जो आय एवं रोज़गार का सृजन करते हैं।
- अर्थव्यवस्था:** भूमि प्रकार का मूल्यवान परसिंपत्ति है जो निवास को आकर्षित कर सकती है, औद्योगिक कार्यक्रम को बढ़ावा दे सकती है और विकास को प्रेरित कर सकती है। विशेष आरथिक क्षेत्र (Special Economic Zones- SEZs) भूमि-आधारित पहलों के उदाहरण हैं जिनका उद्देश्य नियमित उत्पादन के लिये अति-उदारीकृत प्रक्रियाएँ (hyper-liberalized enclaves) का नियमांनय करना है।
 - भूमि जिब हस्तांतरण की जाती है तो कुछ शरतों और छूटों के अधीन दीरघकालिक पूँजीगत लाभ भी उत्पन्न कर सकती है।
- प्राकृतिक संसाधन:** भूमि में खननि, जल और वन जैसे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भी शामिल होते हैं। ये संसाधन मानव उद्योग और वाणिज्य के लिये अत्यंत उपयोगी हैं।
- संस्कृति और पहचान:** भूमि लिंगों के लिये पहचान और संबंधित (belongingness) का भी एक स्रोत हो सकती है। यह एक विशेष संस्कृतिया समुदाय से जुड़ी हो सकती है और यह धार्मिक एवं आध्यात्मिक अभ्यासों में एक भूमिका निभा सकती है।

भारत में भूमि अभलिख प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- वाद-विवाद में कमी लाना:** भारत में न्यायालय में लंबते मामलों में भूमि संबंधी विवादों का एक बड़ा भाग है, जिनके निपटान में दीर्घ समय और लागत का निवास होता है। एक व्यापक एवं पारदर्शी भूमि अभलिख प्रबंधन प्रणाली सरकार द्वारा समर्थित स्पष्ट एवं सुरक्षित स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के माध्यम से ऐसे विवादों के दायरे एवं आवृत्तिकों को कम कर सकती है।
- पारदर्शन में सुधार:** भारत में भूमि अभलिख प्रणाली त्रुटिपूरण, पुराने और सरकार के विभिन्न विभागों एवं सतरों पर खंडित होने की स्थिति रिखते हैं। एक व्यापक एवं पारदर्शी भूमि अभलिख प्रबंधन प्रणाली भूमि अभलिख के डिजिटलीकरण और उन्हें स्थानकी डेटा एवं अन्य डेटाबेस (जैसे आधार, कर अभलिख आदि) से जोड़ने के माध्यम से उनकी गुणवत्ता एवं अभिमयता में सुधार कर सकती है।
- विकास को बढ़ावा:** भूमि प्रकार का मूल्यवान संपत्ति है जो निवास को आकर्षित कर सकती है, औद्योगिक कार्यक्रम को बढ़ावा दे सकती है और विकास को प्रेरित कर सकती है। एक व्यापक एवं पारदर्शी भूमि अभलिख प्रबंधन प्रणाली लेन-देन लागत, जोखमि और अनश्चितिताओं को कम करके भूमि बाज़ारों एवं लेन-देन के लिये अनुकूल वातावरण का नियमांनय कर सकती है। यह भूस्वामियों को संपारशवकि के रूप में अपने भूमि स्वामित्व का उपयोग कर करेगा।

बीमा एवं बाज़ार पहुँच पाने में सक्षम बना सकती है।

- **समानता सुनिश्चिति करना:** एक व्यापक एवं पारदर्शी भूमि अभलिख प्रबंधन प्रणाली भूमि सुधारों के कार्यान्वयन का समर्थन कर सकती है जिसका उद्देश्य समाज के भूमिहीन और हाशमि पर स्थिति वर्गों के बीच भूमिका पुनर्वर्तित करना है। यह महलियों और अन्य कमज़ोर समूहों को उनके भूमि अधिकारों को मान्यता देने और भूमि संबंधी सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाने के रूप में सशक्त बना सकता है।

राष्ट्रीय भूमि अभलिख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP)

राष्ट्रीय भूमि अभलिख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) एक [केंद्र प्रयोजनीय योजना](#) थी जिसे वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा देश में भूमि अभलिख प्रणाली को आधुनिक बनाने और स्वामतिव की गारंटी के साथ नियमित प्रणाली को लागू करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। NLRMP को वर्ष 2016 में केंद्र द्वारा **100% वित्तीय प्रणाली** के साथ [केंद्रीय क्षेत्र की योजना](#) के रूप में संशोधित किया गया और [डिजिटल इंडिप्रिया भूमि अभलिख आधुनिकीकरण कार्यक्रम \(DILRMP\)](#) के रूप में नया नामकरण किया गया।

DILRMP की मुख्य बातें:

- **भूखंडों के लिये एक विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या** (Unique Land Parcel Identification Number- ULPIN) या भू-आधार (Bhu-Aadhaar) संख्या निरिदेशित की गई है। यह भू-नियमित पर आधारित 14 अंकों की अल्फान्यूमेरिक यूनिक आईडी है, जो कसी भूखंड के स्वामतिव विवरण (आकार और भू-अवस्थति सहित) को प्राप्त करने के लिये अखलि भारतीय संख्या के रूप में कार्य करेगी।
- वलिखी/दस्तावेजों (deeds/documents) के पंजीकरण के संबंध में वभिन्न राज्यों में प्रचलित भनिन-भनिन प्रणालियों को संबोधित करने के लिये [राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली](#) (National Generic Document Registration System- NGDRS) नामक एक सार्वभौमिक प्रणाली विकसित की गई है।
- देश में भूमि शासन में विद्यमान भाषाई बाधाओं की समस्या को दूर करने के लिये संवधिन में उल्लिखित सभी **22 अनुसूचित भाषाओं** में अधिकार-अभलिख (Records of Rights) का लपित्यरण किया गया है।
- DILRMP योजना जाति, आय एवं अधिवास प्रमाणपत्र प्रदान करने जैसी सेवाएँ प्रदान करने और फसल प्रोफाइल, फसल बीमा एवं क्रेडिट सुवधाओं/बैंकों के लिये ई-लिंकेज के संबंध में ऑनलाइन सूचना प्रदान करने को भी सुगम बनाएगी।
- एक व्यापक भूमि अभलिख प्रबंधन प्रणाली लंबे समय से लंबति मध्यस्थता मामलों एवं सीमा-संबंधी विवादों को सौहारदप्रण ढंग से हल करने में मदद करेगी, जिससे न्यायपालिका एवं प्रशासन पर बोझ कम होगा।

DILRMP कसि प्रकार लाभप्रद सदिध हो सकता है?

- **भूमि अभलिखों की गुणवत्ता और अभिगम्यता में सुधार:**
 - DILRMP का उद्देश्य भूमि-स्वामतिव और लेन-देन (जैसे बक्री वलिख, विस्त अभलिख, बंधक एवं पट्टे के दस्तावेज, भू-कर मानचित्र आदि) के शाब्दिक एवं स्थानिक अभलिख को डिजिटलीकृत करना और उन्हें अद्यतन करना है।
 - ये अभलिख आम लोगों के लिये ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं और नियमित रूप से अपडेट किये जाते हैं। यह भूमि डेटा में व्याप्त तरुणियों, वसिंगतियों और अंतरालों को कम करने तथा उन्हें अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाने में मदद करता है।
- **मुकदमेबाजी और धोखाधड़ी को कम करना:**
 - DILRMP का उद्देश्य स्वामतिव की गारंटी के साथ नियमित भूमि-स्वामतिव प्रणाली को लागू करना है, जिसका अभिप्राय है कि भूमि अभलिख भूमि के स्वामतिव का एक नियमित प्रमाण प्रदान करेंगे और सरकार द्वारा समर्थित होंगे।
 - स्वामतिव धारक (title holder) अन्य दावेदारों द्वारा कसी भी चुनौती या विवाद से सुरक्षित होंगे और स्वामतिव में कसी भी तरुणीसे उत्पन्न हानि के मामले में सरकार द्वारा क्षतिपूरित के हकदार होंगे।
 - यह भूमि संबंधी विवादों और धोखाधड़ी के दायरे एवं आवृत्तियों को कम करने में मदद करेगा, जो भारत में न्यायालय में लंबति मामलों के एक बड़े भाग का नियमण करते हैं।
- **विकास और वृद्धि को बढ़ावा:**
 - DILRMP का उद्देश्य लेन-देन की लागत, जोखमि और अनश्चितिताओं को कम करके भूमि बाज़ारों एवं लेन-देन के लिये अनुकूल वातावरण का नियमण करना है।
 - यह भूमि-स्वामतियों को संपारश्वकि के रूप में अपने भूमि-स्वामतिव का उपयोग कर ऋण, बीमा और बाज़ार पहुँच पाने में सक्षम बनाता है।
 - यह नविश को आकर्षित करने, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और कृषि, अवसंरचना, आवास जैसे वभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- **समानता और अधिकारता सुनिश्चिति करना:**
 - DILRMP का उद्देश्य भूमि सुधारों के कार्यान्वयन का समर्थन करना है, जो समाज के भूमिहीन और हाशमि पर स्थिति वर्गों के बीच भूमि का पुनर्वर्तित करना है।
 - यह महलियों और अन्य कमज़ोर समूहों को उनके भूमि अधिकारों को मान्यता देने और भूमि संबंधी सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाने के रूप में सशक्त बनाता है।
 - इससे उनकी आजीविका, गरमिए और सामाजिक स्थितियों में सुधार लाने में मदद मिलती है।

भूमि अभलिख डिजिटलीकरण से संबंध चुनौतियाँ

- राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग का अभाव:

- भूमिराज्य सूची का विषय है और DILRMP का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की इच्छा एवं सहयोग पर निर्भर करता है।
- कुछ राज्य राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी या तकनीकी बाधाओं जैसे वभिन्न कारणों से DILRMP को अपनाने के प्रतिअनिवार्य या प्रयाप्त सुस्त हैं।
- भूमिकानुनों, नीतियों, प्रक्रयियाओं और प्रणालयों के संदर्भ में वभिन्न राज्यों के बीच समन्वय एवं मानकीकरण का भी अभाव है।
- अप्रयाप्त संसाधन और क्षमता:
 - DILRMP को देश में भूमिअभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के बृहत कार्य को पूरा करने के लिये प्रयाप्त वित्तीय, मानवीय और तकनीकी संसाधनों एवं क्षमता की आवश्यकता है।
 - लेकिन कार्यान्वयन के वभिन्न सतरों पर धन, करमचारियों, उपकरणों और अवसंरचना की कमी है।
 - भूमिअभिलेख प्रबंधन के लिये आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों के उपयोग के मामले में संबद्ध अधिकारियों और कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता है।
- हतिधारकों के बीच जागरूकता और भागीदारी की कमी होना:
 - DILRMP के सफल कार्यान्वयन हेतु भू-स्वामियों, खरीदारों, विक्रेताओं, कसिनों, बचौलियों जैसे वभिन्न हतिधारकों (जो भूमिअभिलेख प्रणाली में रूपांतरण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं) की सक्रिय संलग्नता एवं भागीदारी की आवश्यकता है।
 - लेकिन इन हतिधारकों में DILRMP के लाभों एवं प्रक्रयियाओं के बारे में जागरूकता तथा संवेदनशीलता का अभाव देखा जाता है।

आगे की राह:

- राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ावा देना:
 - DILRMP से संबंधित चुनौतियों एवं समस्याओं को दूर करने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।
 - इस क्रम में वभिन्न राज्यों में प्रचलित भूमिसंबंधित कानूनों, नीतियों, प्रक्रयियाओं और प्रणालयों को सुसंगत एवं सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इन्हें DILRMP की सर्वोत्तम प्रक्रयियाओं और अनुभवों को प्रस्पर साझा करने की भी आवश्यकता है।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करना:
 - DILRMP में होने वाली कसी भी तरह की हेरफेर या भ्रष्टाचार के विद्युद्ध केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
 - भूमिसर्वेक्षण, डिजिटलीकरण, सत्यापन और स्वामित्व प्रदान करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेहता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
 - DILRMP से उत्पन्न होने वाले कसी भी विवाद या शक्यायत के समाधान हेतु एक शक्यायत निवारण तंत्र स्थापित करने की भी आवश्यकता है।
- प्रयाप्त संसाधन जुटाने के साथ क्षमता विकास पर बल देना:
 - DILRMP के कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रयाप्त धन, कारमकि, उपकरण और अवसंरचनात्मक ढाँचा प्रदान करने की आवश्यकता है।
 - भूमिरकिंरड प्रबंधन हेतु आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों के उपयोग के संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
 - इस संदर्भ में दक्षता बढ़ाने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का भी लाभ उठाया जा सकता है।
- हतिधारकों के बीच जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना:
 - केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा DILRMP के लाभों एवं प्रक्रयियाओं के बारे में संलग्न हतिधारकों को बताना एवं इस संदर्भ में संवेदनशीलता विकसित करने की आवश्यकता है।
 - सपष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करने के माध्यम से DILRMP के बारे में हतिधारकों की आशंकाओं या भ्रामक धारणाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
 - भूमिअभिलेख प्रबंधन की प्रक्रिया में हतिधारकों की संलग्नता एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है।

अभ्यास प्रश्न: सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) एक पारदर्शी भूमिअभिलेख प्रणाली विकसित करने के लिये शुरू किया गया था। इस योजना के लाभों एवं चुनौतियों की चर्चा करते हुए आगे की राह बताइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

?????????

पर. स्वतंत्र भारत में भूमिसुधारों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) हवबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रति थे, न कियक्तिगत जोत पर।
- (b) भूमिसुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषिभूमिप्रदान करना था।
- (c) इसके परिणामस्वरूप नकदी फसलों की खेती, कृषि का प्रमुख रूप बन गई।
- (d) भूमिसुधारों ने हवबंदी सीमाओं को कसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी।

उत्तर: (b)

?????????

पर. कृष्णविकास में भूमिसुधारों की भूमिका की विविचना कीजयि। भारत में भूमिसुधारों की सफलता के लयि उत्तरदायी कारकों को चिह्निति कीजयि। (2016)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/digitisation-of-land-records>

